







# चौथे स्तंभ की सजगता से ही जनतंग्र को मजबूती

विश्वनाथ सचदव

देश का प्रधानमंत्री कुछ भी कह उस गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उस पर चर्चा भी होनी चाहिए। पर हाल ही में पटना के एक चुनाव में आयोजन में उन्होंने एक पत्रकार से जो कुछ कहा, उसके बायाय उनका एक पत्रकार से रोड शो के दौरान बात करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले दस साल के शासनकाल में हमारे प्रधानमंत्री ने देश में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया है। हाँ, कुछ पत्रकारों से अलग-अलग बातचीत अवश्य करते रहे हैं, पर इन सारी मुलाकातों के 'प्रायोजित' ही समझा जाता रहा है। यह भी अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं है कि ऐसी मुलाकातों में से एक जो सबसे ज्यादा चर्चित रही है उसमें प्रधानमंत्री से 'आप आम कैसे खाते हैं' जैसे सवाल पूछे गये थे। बहरहाल एक टीवी चैनल के पत्रकार से रोड शो के दौरान हुई बातचीत की घटना को अखबारों की सुर्खी बनना ही था। चैनलों पर भी इस मुलाकात को लेकर विशेष चर्चाएं आयोजित हुईं। यह भले ही किसी को याद न रहा हो कि इस बातचीत में क्या मुद्दे उठाये गये, पर यह सब को याद होगा कि दस साल की चुप्पी के बाद प्रधानमंत्री ने इस तरह से पत्रकार वेबसाइटों का जवाब दिया। महत्वपूर्ण यह भी है कि इस इंटरव्यू के बाद समाचार चैनलों और अखबारों के प्रतिनिधियों से प्रधानमंत्री की बातचीत का दौर-सा चल पड़ा। क्यास इस बारे में लगाये जा रहे हैं कि अचानक प्रधानमंत्री जी को पत्रकारों से इस तरह बात करना ज़रूरी क्यों लगने लगा है। और चर्चा इस बात की भी है कि आम-चुनाव के तीन दौर समाचार होने के बाद मतदाता की 'उदासीनता' देखकर राजनेताओं, विशेषकर सत्तारूढ़ दल भाजपा, के नेताओं को लगाने लगा है कि रणनीति कुछ बदलने की ज़रूरत है।

इस बात का लकर भत्तमद हा सकत ह, वामपंथी राव हा सकता ह, पर मीडिया को लेकर प्रधानमंत्री के रुख में आया यह परिवर्तन स्वागतोग्य है तमीद की जानी चाहिए कि पत्रकार-समाज इस अवसर का समुचित उपयोग करने की कोशिश करेगा। उमीद यह भी की जानी चाहिए कि यहिं पत्रकारों को आगे भी ऐसे अवसर मिलते हैं तो पत्रकार निर्भीकता और ईमानदारी के साथ सवाल पूछेंगे और उहें समुचित उत्तर मिलेंगे। बात सिफ सवाल पूछने और उत्तर मिलने तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, यदि किसी सवाल का सम्यक उत्तर नहीं मिलता तो पत्रकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निर्भीकतापूर्वक पूछा उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करेगा। इस संदर्भ में मुझे एक बड़े अखबार के बड़े पत्रकार की ऐसी ही बातचीत याद आ रही है। पत्रकार ने प्रधानमंत्री से पूछा था— चुनाव प्रचार में इस बार धर्म आधारित भाषण ज्यादा हो रहे हैं, आप इहें कैसे देखते हैं? इस प्रश्न का जो उत्तर प्रधानमंत्री ने दिया, वह इस प्रकार छपा है = 'आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखिए। उसके शहजादे का भाषण देखिए। मनमोहन सिंह का सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। उसमें सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की भावना नज़र आयेगी। तुष्टीकरण कांग्रेस का मूल स्वभाव बन गया है। इसके बिन उनकी राजनीति नहीं चल सकती। यह मेरा दायित्व है कि मैं तथ्यों को देश

किस साच के तहत काम करत है, यदश का जानना आवश्यक हा। पता नहीं जो चार सवाल और उनके उत्तर अखबार में छपे हैं इसके अलावा भी प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा था, लेकिन यह एक उत्तर पूछे गये सवाल के साथ न्याय नहीं करता। चुनाव में धर्म आधारित भाषण की बात सभी दलों पर लागू होती है। प्रधानमंत्रीजी से यह पूछा जाना चाहिए था कि सवाल भाजपा के नेताओं से भी संबंधित है और उनसे यह अपेक्षा है कि वे बतायेंग कि भाजपा के नेता ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन यह पूछा नहीं गया और न ही स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में कुछ कहना जरूरी समझा। यह पहली बार नहीं है कि चुनाव प्रचार में राजनीतिक दलों द्वारा धर्म का सहारा लेने की बात उठी है। लगभग हर चुनाव में धर्म की बैसाखी का सहारा लेकर चुनावी लाभ लेने की कोशिशें हुई हैं। हमारा संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। धर्म के नाम पर मतदाता को बांटना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं समझा जाना चाहिए। ‘राम मंदिर पर बाबरी ताला’ जैसी बात कहना अपर्याप्त आप में मर्यादा की लक्षण रेखा के उल्कंघन से कम नहीं है। किसी राजनेता का किसी भी मंदिर में जाना कर्तव्य गुलत नहीं है। हर एक को अपनी आस्था और श्रद्धा का सम्मान करने का अधिकार है। इस संदर्भ में किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। शिकायत सिर्फ इस बात की होर्न

अपमान कर रह हा धम आधारत भाषण वाल सवाल के उत्तर म प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए था कि वह धर्म के इस दुरुपयोग का समर्थन न करते; उन्हें कहना चाहिए कि पंथ-निरपेक्ष देश में धर्म के नाम पर राजनीति करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। उदाहरण हैं हमारे यहां जारी राजनेताओं को ऐसे अपराध की सजा मिली है, पर अधिसंचय राजनेता ऐसे उदाहरणों की परवाह नहीं करते। धार्मिक आधार पर तुष्टीकरण की नीति व समर्थन नहीं किया जा सकता, पर धर्म के नाम पर धर्वाकरण की कोशिश भी तो छोटा अपराध नहीं है। यह सचमुच दुर्भाग्य की बात है कि आम चुनाव के अधबीच हिंदू-मुसलमान की बात होने लगी है। चुनाव प्रचार व शुरुआत में ऐसी नहीं था, पर पता नहीं शीर्ष राजनेताओं को इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होने लगी है?

चुनाव के चार दौरों के पूरा होने के बाद यदि एक और बात ज सामने आयी है, वह मतदाता की अपेक्षाकृत उदासीनता है। अपेक्षा से कम मतदाताओं का मतदान के लिए आना सबके लिए चिंता की बात होना चाहिए। अधिकाधिक मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुँचें यह जनतंत्र का सफलता का एक संकेत है। लेकिन यदि धर्म के नाम पर मतदाताओं का लुभाने की कोशिश ज़रूरी है तो ऐसी राजनीति देश को नहीं चाहिए। ह

नागरक, चाहे वह किसा भाषम का ही, पहल भारतीय हो। यह अर ऐसे बातें प्रधानमंत्री को धर्म आधारित भाषणों वाले प्रश्न के उत्तर में कहनी चाहिए थीं। यदि उन्होंने अपने कुछ कारणों से ऐसा नहीं किया तो पत्रकारों का काम था उन्हें यह अहसास कराना कि प्रश्न धर्म के नाम पर की जाने वाली राजनीति के औचित्य का था। बहरहाल, कारण कुछ भी रहे हों, प्रधानमंत्री की यह पहल एक अच्छी शुरुआत है। यह सिलसिला, दस साल पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था। रहे होंगे कुछ भी कारण ऐसा न कर पाने अथवा न हो पाने के, पर स्वस्थ जनतंत्र में राजनीति और पत्रकारिता का स्वस्थ रिश्ता होना ज़रूरी है। पत्रकारिता का दायित्व है कि वह विधायिका को जागरूक बनाये रखने के प्रति सजग और सक्रिय रहे और विधायिका का कर्तव्य है कि वह इन स्वस्थ रिश्तों को कमज़ोर न पड़ने दे। पत्रकारिता को जनतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। इस स्तंभ की मज़बूती जनतंत्र की मज़बूती का एक आधार है। अर्सा हुआ, प्रधानमंत्री एक इंटरव्यू को अधूरा छोड़कर उठ गये थे। उठते-उठते उन्होंने कहा था, ‘ज्हमारी दोस्ती बनी रहे।’ उम्मीद की जानी चाहिए कि पटना की उस रैली में प्रधानमंत्री ने यो पहल की है, वह इस ‘दोस्ती’ को बनाये रखने में मददगार होगी। स्वस्थ राजनीति, स्वस्थ पत्रकारिता और स्वस्थ रिश्ते हमारे जनतंत्र को सार्थकता देंगे।

इसकी पुनरावृति लक सकती थी, लेकिन समाधान निकालने के किसी भी तरीके पर सरकार की ओर से कोई चिंतन नहीं किया गया। इस कारण यह समस्या आज पूरे देश में तेजी से पैर पसारती जा रही है। इसका मुख्य कारण देश विदेशी कार्यों को अंगाम देने वाली राजनीति को माना जा सकता है। कश्मीर का सबसे जघन्य सच यह है कि वहाँ से जो हिन्दू धर्म को पूरी तरह से मानते थे, उन्हें ही भगाया गया, बाकी सब मुसलमान बन गए। यह एक प्रकार से धर्मान्तरण का ही खेल था। धर्मान्तरण का खेल कौन चला रहा है, यह भी लगभग सभी जानते हैं। महात्मा गांधी ने धर्मान्तरण के बारे में कहा था कि धर्मान्तरण के कारण एक व्यक्ति केवल दूसरे सम्प्रदाय को ही स्वीकार नहीं करता, बल्कि देश का एक और दुश्मन पैदा हो जाता है। इस बात से यह सदैश मिलता है कि ईसाई संस्थाएं और इस्लामिक संस्थाएं अपने विचार को फैलाने के लिए जो कार्यक्रम चलाती हैं, वह भारत के लिए किसी न किसी रूप से ठीक नहीं जा सकती है। वयोंकि इन संस्थाओं के विचार पूरी तरह से भारतीय विचार से सामंजस्य नहीं रखते। वास्तव में विश्व के किसी भी देश में सबसे पहले यही शिक्षा दी जाती है कि वह उस देश की संस्कृति से जुड़े रहे। याहे वह ईसाई देश हो या फिर मुस्लिम देश ही वयों न हो? सबसे पहली बात यही होती है कि देश भक्त बने, केवल अपने संप्रदाय का भक्त नहीं। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है।

www.Xamini.com | 188 of

इति मैं जनस्यात्मा स्वयंत्रता के तिर्हुता।

# ગાર્દી ને જાહેરવા જેસાં હતુલન કરીએ

अभी हाल ही में ज

43.15 प्रातिशत का दस सूमुस्लमा का जनसंख्या बढ़ रहा है, जबकि हिन्दू की जनसंख्या में 7.82 प्रतिशत की गिरावट सामने आई है। यानी आनुपातिक दृष्टि से भारत में हिन्दुओं की संख्या लगातार घट रही होती जा रही है। चिंता यह नहीं है हिन्दू कम क्यों होते जा रहे हैं, बल्कि चिंता इस बात की है कि मुसलमानों की जनसंख्या में यह अद्वितीय कहाँ घुसपैठ के कारण तो नहीं है। अगर यह सत्य है तो और नीति गंभीर चिंता का विषय है। इसी घुसपैठ के चलते भारत के नौ राज्यों में आज हिन्दू अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ गया है। इसके नारण देश में विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा हो रहीं हैं। सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है, क्योंकि संसाधन सीमित होने के बाद भी

A large, dense crowd of people, predominantly men, is gathered in an outdoor setting. They are all actively engaged in capturing the moment with their mobile phones and cameras. The crowd is a mix of ages and ethnicities, with many men wearing traditional caps and casual wear. The atmosphere appears to be one of excitement or a significant public gathering.

अप्रत्यक्ष तौर पर देश में होने वाले चुनावों के लिए प्रार्थना करके कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही थी। अगर कांग्रेस को समर्थन देने की बात सही मानी जा सकती है तो यह भी तय है कि उनको हिन्दू समाज को ईसाई बनाने की खुली छूट भी मिल सकती है। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद से ही हिन्दुओं की संख्या में लगातार कमी होती जा रही है और जहां भी हिन्दू कम हुआ है, वहां समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इसका मतलब यह भी है कि हिन्दू जिस राज्य में भी बहुतायत में होता है वहां शांति का वातावरण होता है, देश का हिन्दू समस्या नहीं समाधान का हिस्सा है, समाधान का हिस्सा हिन्दू समाज की संस्कृति है। आज कई राज्यों में हिन्दुओं की संख्या में बहुत बड़ी कमी देखी जा रही है। इस कारण देश के नौ राज्यों में हिन्दुओं का अल्पसंख्यक का दर्जा मिल सकता है। लक्ष्यद्वीप में 2.5, मिजोरम में 2.75, नागालैंड में 8.75, मेघालय में 11.53, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 28.44, अरुणाचल प्रदेश में 29, मणिपुर में 31.39 और पंजाब में 38.40 प्रतिशत हिन्दू हैं। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में भी कई जिलों में हिन्दुओं की जनसंख्या में कमी आती जा रही है। इसमें उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल के जिलों के नाम शामिल किए जा सकते हैं। यहां चिंतन की बात यह नहीं है कि इन राज्यों में हिन्दुओं को अल्पसंख्यकों के अधिकार मिलने चाहिए, बल्कि चिंतन इस बात का करना चाहिए कि इन राज्यों में ऐसे कौन से कारण रहे, जिसके चलते हिन्दू अल्पसंख्यक हो गया। इसका मूल कारण क्या है, इसका

कर्हीं भय के कारण हिन्दू पलायन की स्थिति दिखाई देगी। कश्मीर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, वहां एक समय हिन्दुओं की संख्या प्रभावी थी, लेकिन अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान परस्त व्यक्तियों ने हिन्दुओं पर अत्याचार किए, इसके कारण आज घाटी हिन्दू विहीन हो गई है। पाकिस्तान परस्त मानसिकता वाले कट्टरपंथी मुसलमान आज भी देश के कई हिस्सों में योजनापूर्वक हिन्दुओं को प्रताड़ित करते हैं, जिससे हिन्दू किसी अन्य स्थान पर चले जाएं। उत्तरप्रदेश के कैराना और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में ऐसे ही हालात निर्मित हुए। इन्हाँ ही नहीं कई स्थानों पर हिन्दू समाज अपने त्यौहार खुलकर मनाने की स्थिति में नहीं हैं। सबाल यह भी है कि भारत देश के कई हिस्सों में हिन्दू भय की स्थिति में जीने को मजबूर हो रहा है। सबाल यह है कि क्या हमारा देश अहिन्दूकरण की ओर कदम बढ़ा रहा है। यह देश के हिन्दुओं को समझना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है, जो कभी कश्मीर में हुआ था, वह पूरे देश में दिखाई दे सकता है। देश में इस बात के कई बार स्पष्ट प्रमाण मिल चुके हैं कि भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कुछ राजनीतिक दल इस मामले पर खुलकर घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं, और कुछ मौन रहकर इसको स्वीकृति दे रहे हैं। जो बहुत ही ख़तरनाक है। देश के राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जनसंख्या का यह अनुपातिक असंतुलन क्यों पैदा हो रहा है। इसके निहितार्थ

प्रवास

# ગણારૂ પણ ચિંતા તપજો આક્રોશ કી તપિશ

---

जब हमारी क़

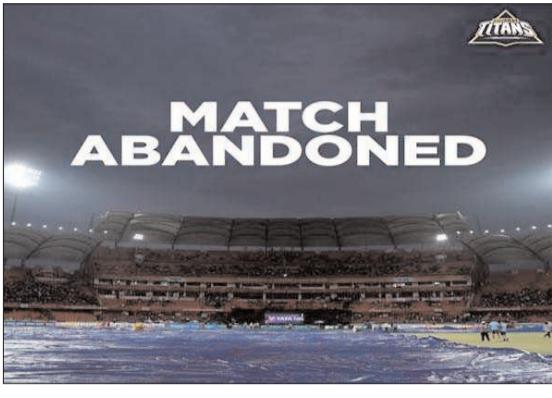
जायपूरा परम्परा (भाजपा) का बहुत बड़े हरेस्त न जानना सुनका १० हजार जन्म-परम्परा की राजधानी श्रीनगर से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद और मीरपुर जैसे प्रमुख शहरों में जनता सरकार से दो-दो हाथ करना चाहती है। जनता पीओके सरकार और देश की संघीय सरकारों से अपना हक मांग रही है। पीओके में जब आंदोलन चल रहा है, तब भारत में चल रहे लोकसभा चुनाव की कैपेनिंग के दौरान पीओके का जिक्र आ रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बीते रविवार को कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) भारत का है, उसे हम लेकर रहेंगे। उल्लेखनीय है कि पीओके को भारत से मिलाने पर भारतीय संसद का एक अहम प्रस्ताव भी है। बहरहाल, पीओके की बिंगड़ी स्थिति की बजह से पाकिस्तान के रहनुमाओं की रातों की नींदें उड़ गई हैं। पाकिस्तान तो भारत के जम्मू-कश्मीर पर बार-बार अपना दावा करता है, पर दुनिया देख रही है कि उसके कब्जे वाला कश्मीर जल रहा है। पीओके की अवाम बिजली की भारी-भरकम बिलों और आटे के आसमान छूटे दामों के कारण आक्रोशित है। वहां पर संकट गहराता जा रहा है। दरअसल, सोशल मीडिया के दौर में पीओके की जनता देख रही है कि भारत के कश्मीर में जनता कम से कम बिजली के बिलों या आटे की आसमान छूटी कीमतों के कारण तो नाराज नहीं है। वहां अन्य मसले हो सकते हैं, पर कुल मिलाकर जीवन सुकून भरा है। पीओके में ताजा हिंसक आंदोलन की ताक्तालिक बजह यह है कि पाकिस्तान सरकार ने आटे की कीमतों को कम करने की मांग को मानने से इंकार कर दिया है। बिजली के बिल कम करने पर तो सरकार आंदोलनकारियों से कोई बात करने तो वैसे भी तैयार नहीं है। दरअसल, पीओके में बवाल तब शुरू हुआ जब अवामी एकशन कमेटी ने ८ मई, २०२४ को अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किए थे। इससे पहले, बीते साल अगस्त में बिजली बिलों पर नए करों को लगाने से स्थिति बिंगड़ने लगी थी। इन करों के विरोध में मुजफ्फराबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू किए थे, जिन्हें स्थानीय व्यापारियों का समर्थन मिला। ये प्रदर्शन जल्दी ही रवालकोट और मीरपुर जिलों तक फैल गए। पिछले साल १७ सितंबर को मुजफ्फराबाद में एक बैठक के बाद, अवामी एकशन कमेटी ने अपने आंदोलन को राज्यव्यापी करने का फैसला किया। इसके बाद पीओके में बिजली बिल जलाये जाने लगे। इसके जबाब में, सरकार ने कई आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया, लेकिन जनता के दबाव के कारण उन्हें रिहा कर दिया। इसके बाद आंदोलनकारियों की तरफ से सरकार को १० सूचीय मांगों की सूची सौंपी गई। इस सूची में आटे पर सब्सिडी और बिजली के बिलों में कमी करने की मांग शामिल थीं। पर, सरकार बिजली बिलों में कमी और आटे के दाम कम करने के लिए तैयार नहीं हुई। यही बजह है कि सरकार की हठधर्मिता से नाराज अवामी एकशन कमेटी ने मुजफ्फराबाद स्थित पीओके विधानसभा तक मार्च करने का आह्वान किया। ९ मई को डोडियाल में एक डिटी कमिशनर पर उस समय हमला किया गया जब उहनें एक भीड़ को तितर-बितर करने के आदेश दिए। १० मई को पीओके के प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद की ओर मार्च करने के लिए निकले, जिसके कारण गंभीर झड़पें हुईं। एक आला पुलिस अफसर की मौत हो गई। इसके बाद पीओके के मुख्यमंत्री अनवर उल हक सरकार को जनता के गुस्से से दो-चार होना पड़ रहा है। हक की छवि एक बेहद कड़क नेता की है। वे बात-बात पर आपा खो देते हैं। पीओके के मीरपुर जिले में ९ मई को एक डिटी कमिशनर को प्रदर्शनकारियों ने बुरी तरह पीटा और उसकी कार को फूंक भी दिया था। फिलहाल लगता तो यही है कि अवामी एकशन कमेटी का अपनी मांगों के समर्थन में चल रहा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगों को मान नहीं लिया जाता। हां, सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच रवालकोट में बातचीत फिर से शुरू हो गई। पर यह देखने वाली बात है कि क्या पाकिस्तान सरकार, जो पीओके सरकार के साथ खड़ी है, प्रदर्शनकारियों की मांगों को स्वीकार करेगी? फिलहाल लगता तो नहीं है कि प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ तो प्रदर्शनकारियों पर एकशन लेने के संकेत दे रहे हैं। पीओके में चल रहे प्रदर्शन पर हमारे उन कश्मीरियों को नजर रखनी चाहिए जिन्हें भारत से सिफारिश कियायें रहती हैं। इस बीच, लगता है कि कांग्रेस नेता मणिशंकर अथवा फारूक अब्दुल्ला को पीओके पर भारतीय संसद में पारित प्रस्ताव की जानकारी ही नहीं है। इसलिए ही ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। इन्हें पता होना चाहिए कि २२ फरवरी, १९९४ बेहद खासमचास दिन है— भारत की कश्मीरी नीति की रोशनी में। उद्दित संसद ने एक प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित करके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके)





## एक नजर

हैदराबाद और गुजरात मैच हुआ रद्द,  
दिल्ली, लखनऊ प्लेऑफ से हुए बाहर



हैदराबाद, एजेंसी। लगातार हो रही बारिश के कारण गुरुवार को सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का 66वां मैच रद्द घोषित कर दिया गया। इसी के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जाइंट्स को बायो-ऑफ से बाहर हो गई है। हैदराबाद में लखनऊ हो रही बारिश के कारण मैच में एक भी गेंद फेंकी नहीं जा सकी और अंपायर नंद किरण और विरेंद्र शर्मा ने मैदान का निरीक्षण किया। अंत आधिकारिक रूप से मैच को रद्द घोषित कर दिया गया। आज का मैच रद्द होने के बाद प्लेऑफ के बने समीकरण के अनुसार दिल्ली कैपिटल्स की टीम नेट रेट (-0.377) होने के कारण आधिकारिक तौर पर बाहर हो गई क्योंकि उनका रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु (आरसीबी) (+0.387) से काफी पीछे है और उनके पास कोई मैच भी नहीं बचा है। जबकि लखनऊ सुपर जाइंट्स (एलएसजी) के लिए प्लेऑफ में प्रवेश पुर्खिल होता है। लखनऊ का नेट रेट -0.787 है। उन्हें बैंगलुरु से ऊपर जाने के लिए कम से कम 400 रुपये मैच जीतना होगा।

**एक बार काम पूरा हो गया तो चला जाऊंगा, फिर कुछ समय नजर नहीं आऊंगा : कोहली**



बैंगलुरु। भारत के सुपरस्टार बलेश्वार विराट कोहली को पता है कि वह हेमशा खेलते नहीं रख सकते लेकिन विदा लेने से पहले वह अपना सबकुछ किटेट कैरियर को देना चाहते हैं और उनका कहना है कि एक बार जाने के बाद वह कुछ समय नहीं भी आये। कोहली आईपीएल में इस सत्र में अब तक का किटकॉर्ड आरावां शतक जड़ चुके हैं। उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु के लिये 13 मैचों में 661 रन बनाये हैं। आरसीबी द्वारा सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो में 35 वर्ष के कोहली ने कहा कि मलाल के बिना जीने की ललक ही उनकी प्रेरणा है। उन्होंने कहा, “मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ा चाहता ताकि बाद में कोई पछताका नहीं हो।” एक बार काम पूरा हो जाये तो मैं चला जाऊंगा और फिर कुछ समय नजर नहीं आऊंगा।” उन्होंने कहा, “जब तक मैं खेल रहा हूं, अपना सब कुछ खेल को देना चाहत हूं। यहीं मेरी प्रेरणा है।” कोहली ने कहा, “हर खिलाड़ी के कैरियर का अंतिम चरण जो जीत जाती है तो उसके दस अंक होंगे जिससे वह आखिरी स्थान पर रहने से बच सकते हैं।

**दिल्ली उच्च न्यायालय ने एनआरएआई की ओलंपिक चयन नीति को बरकरार रखा**



नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) द्वारा बनाई गई 2024 पेरिस ओलंपिक चयन नीति को बरकरार रखा है। कोई ने यह आदेश एक शूटर द्वारा उसे ओलंपिक चयन ट्रायल में शामिल न किए जाने को लेकर दायर की गई याचिका खारिज होने के बाद सुनाया। धनानक्रम पर प्रतिक्रिया ब्यक्त करते हुए, एनआरएआई के महासचिव के, सुल्तान सिंह ने गुरुवार को एक आधिकारिक बयान में कहा, ओलंपिक खेलों 2024 के लिए हमारी चयन नीति निष्पक्ष, उचित और पारदर्शी है। सभी एथलीटों को उचित मौका दिया गया है। निशानेवाजों के क्लालीफाई करने के लिए पांतीसी (नीति) अधिक समर्विशी है। भारतीय निशानेवाजी दल ने 26 जुलाई, 2024 को शुरू होने वाले आगामी पेरिस 2024 खेलों के लिए प्रत्येक राइफल और पिस्टल में से प्रत्येक ने अधिकतम आठ कोटा हासिल किए हैं। जबकि राइफल और पिस्टल में से प्रत्येक ने अधिकतम आठ कोटा हासिल किए हैं। जबकि राइफल और पिस्टल में से प्रत्येक ने अधिकतम आठ कोटा हासिल किए हैं। जबकि राइफल और पिस्टल में से प्रत्येक ने अधिकतम आठ कोटा हासिल किए हैं।

## जीत के साथ आईपीएल से विदा लेना चाहेंगे मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जाइंट्स

मुंबई, एजेंसी। आईपीएल प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जाइंट्स शुक्रवार को बानखेड़े स्टेडियम पर अपने आखिरी मैच में जीत के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जाइंट्स के टीमें प्लेऑफ से बाहर हो गई हैं। हैदराबाद में लखनऊ हो रही बारिश के कारण मैच में एक भी गेंद फेंकी नहीं जा सकी और अंपायर नंद किरण और विरेंद्र शर्मा ने मैदान का निरीक्षण किया। अंत आधिकारिक रूप से मैच रद्द घोषित कर दिया गया। आज का मैच रद्द होने के बाद प्लेऑफ के बने समीकरण के अनुसार दिल्ली कैपिटल्स की टीम नेट रेट (-0.377) होने के कारण आधिकारिक तौर पर बाहर हो गई क्योंकि उनका रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु (आरसीबी) (+0.387) से काफी पीछे है और उनके पास कोई मैच भी नहीं बचा है। जबकि लखनऊ सुपर जाइंट्स (एलएसजी) के लिए प्लेऑफ में प्रवेश पुर्खिल होता है। लखनऊ का नेट रेट -0.787 है। उन्हें बैंगलुरु से ऊपर जाने के लिए कम से कम 400 रुपये मैच जीतना होगा।

केंपेंआर से 98 रुपये मैच के बाद उसे सनराइजर्स हैदराबाद ने दस विकेट से और दिल्ली कैपिटल्स से विदा लेने की कोशिश करेंगी। मुंबई इंडियंस का पहले ही दौड़ से बाहर हो चुकी है जबकि लखनऊ सुपर जाइंट्स आगे आखिरी मैच में भी अंत तक चार मैच पहुंचने की जीत दर्ज करती है तो भी उसके अंतिम चार मैच पहुंचने की कोशिश करती है। तीन मैचों में लगातार हार से लखनऊ ने अंक भी गंवाये और रनरेट भी खराब हो गया।

केंपेंआर से 98 रुपये मैच के बाद उसे सनराइजर्स हैदराबाद ने दस विकेट से और दिल्ली कैपिटल्स से विदा लेने की कोशिश करेंगी। मुंबई इंडियंस का पहले ही दौड़ से बाहर हो चुकी है जबकि लखनऊ सुपर जाइंट्स (एलएसजी) के लिए प्लेऑफ में प्रवेश पुर्खिल होता है। लखनऊ का नेट रेट -0.787 है। उन्हें बैंगलुरु से ऊपर जाने के लिए कम से कम 400 रुपये मैच जीतना होगा।

सत्र विश्व कैपिटल्स का पहले ही दौड़ से विदा लेने की कोशिश करेंगी। मुंबई इंडियंस का पहले ही दौड़ से बाहर हो चुकी है जबकि लखनऊ सुपर जाइंट्स (एलएसजी) के लिए प्लेऑफ में प्रवेश पुर्खिल होता है। लखनऊ का नेट रेट -0.787 है। उन्हें बैंगलुरु से ऊपर जाने के लिए कम से कम 400 रुपये मैच जीतना होगा।

भी हरफनमौला की भूमिका बखूबी नहीं निभा सके। सूर्यकुमार यादव ने तीन अंधशक्त के बाद उसके अंत तक 13 मैचों में बस चार जीत सकी और एक शतक जमाकर अतिव्याप्ति शामिल किया। लखनऊ के कसान के एल राहुल ने तीन अंधशक्त के बाद उसके अंत तक 13 मैचों में ट्रॉफी रेट से 465 रुपये मैच पहले ही दौड़ से बाहर हो चुकी है। उनका स्ट्राइक रेट रेट से 424 रुपये मैच पहले ही दौड़ से बाहर हो चुकी है।

भी हरफनमौला की भूमिका बखूबी नहीं निभा सके। सूर्यकुमार यादव ने तीन अंधशक्त के बाद उसके अंत तक 13 मैचों में बस चार जीत सकी और एक शतक जमाकर अतिव्याप्ति शामिल किया। लखनऊ के कसान के एल राहुल ने तीन अंधशक्त के बाद उसके अंत तक 13 मैचों में ट्रॉफी रेट से 465 रुपये मैच पहले ही दौड़ से बाहर हो चुकी है। उनका स्ट्राइक रेट रेट से 424 रुपये मैच पहले ही दौड़ से बाहर हो चुकी है।

भी हरफनमौला की भूमिका बखूबी नहीं निभा सके। सूर्यकुमार यादव ने तीन अंधशक्त के बाद उसके अंत तक 13 मैचों में बस चार जीत सकी और एक शतक जमाकर अतिव्याप्ति शामिल किया। लखनऊ के कसान के एल राहुल ने तीन अंधशक्त के बाद उसके अंत तक 13 मैचों में ट्रॉफी रेट से 465 रुपये मैच पहले ही दौड़ से बाहर हो चुकी है। उनका स्ट्राइक रेट रेट से 424 रुपये मैच पहले ही दौड़ से बाहर हो चुकी है।

भी हरफनमौला की भूमिका बखूबी नहीं निभा सके। सूर्यकुमार यादव ने तीन अंधशक्त के बाद उसके अंत तक 13 मैचों में बस चार जीत सकी और एक शतक जमाकर अतिव्याप्ति शामिल किया। लखनऊ के कसान के एल राहुल ने तीन अंधशक्त के बाद उसके अंत तक 13 मैचों में ट्रॉफी रेट से 465 रुपये मैच पहले ही दौड़ से बाहर हो चुकी है। उनका स्ट्राइक रेट रेट से 424 रुपये मैच पहले ही दौड़ से बाहर हो चुकी है।

भी हरफनमौला की भूमिका बखूबी नहीं निभा सके। सूर्यकुमार यादव ने तीन अंधशक्त के बाद उसके अंत तक 13 मैचों में बस चार जीत सकी और एक शतक जमाकर अतिव्याप्ति शामिल किया। लखनऊ के कसान के एल राहुल ने तीन अंधशक्त के बाद उसके अंत तक 13 मैचों में ट्रॉफी रेट से 465 रुपये मैच पहले ही दौड़ से बाहर हो चुकी है। उनका स्ट्राइक रेट रेट से 424 रुपये मैच पहले ही दौड़ से बाहर हो चुकी है।

भी हरफनमौला की भूमिका बखूबी नहीं निभा सके। सूर्यकुमार यादव ने तीन अंधशक्त के बाद उसके अंत तक 13 मैचों में बस चार जीत सकी और एक शतक जमाकर अतिव्याप्ति शामिल किया। लखनऊ के कसान के एल राहुल ने तीन अंधशक्त के बाद उसके अंत तक 13 मैचों में ट्रॉफी रेट से 465 रुपये मैच पहले ही दौड़ से बाहर हो चुकी है। उनका स्ट्राइक रेट रेट से 424 रुपये मैच पहले ही दौड़ से बाहर हो चुकी है।

भी हरफनमौला की भूमिका बखूबी नहीं निभा सके। सूर्यकुमार यादव ने तीन अंधशक्त के बाद उसके अंत तक 13 मैचों में बस चार जीत सकी और एक शतक जमाकर अतिव्याप्ति शामिल किया। लखनऊ के कसान के एल राहुल ने तीन अंध

